



करेंट अफेयर्स

छत्तीसगढ़

जुलाई

2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़

➤ EWS छात्रों के लिये निशुल्क कोचिंग	3
➤ केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा राज्यवार वार्ता	3
➤ सिंगल विंडो सिस्टम 2.0	4
➤ स्कूलों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन	4
➤ सुशासन और अभिसरण विभाग	5
➤ छत्तीसगढ़ विकास योजनाओं की समीक्षा	6
➤ वित्त आयोग से छत्तीसगढ़ के लिये विशेष अनुदान	7
➤ माओवादी विद्रोह में कमी	7
➤ छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटेरियम	9
➤ छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटेरियम	9
➤ मलेरिया से निपटने के लिये छत्तीसगढ़ की पहल	10
➤ केटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक में खनन	11
➤ विकसित भारत बजट ब्लूप्रिंट	12
➤ छत्तीसगढ़ सरकार एवं ऑपरेशन प्रहार	12
➤ छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने किया सरेंडर	13
➤ छत्तीसगढ़ में खनन हेतु वनों की कटाई	14
➤ छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने किया सरेंडर	15
➤ छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल	16
➤ छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल	16

छत्तीसगढ़

EWS छात्रों के लिये निशुल्क कोचिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पंजीकृत लाभार्थियों को लक्षित करते हुए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु निशुल्क कोचिंग सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की।

- इसमें राज्य के 10 जिलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना के तहत, पंजीकृत श्रमिक और उनके बच्चे अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 4 से 10 महीने की अवधि के लिये निशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं।
- ◆ इस कोचिंग में लोक सेवा आयोग (PSC), छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, कर्मचारी चयन आयोग और बैंकिंग, रेलवे तथा पुलिस भर्ती सहित विभिन्न परीक्षाएँ शामिल हैं।
- पंजीकृत श्रमिकों (जिनकी मृत्यु 9 जून, 2020 से पहले हो चुकी है) के बच्चे पिछली अधिसूचनाओं के अनुसार इस योजना के लिये पात्र हैं।
- ◆ जबकि निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े लोग भी इस पहल का लाभ उठाने के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- कोचिंग हाइब्रिड मोड में उपलब्ध कराई जाएगी, जो उन छात्रों के लिये आसान होगी जो दूरस्थ रूप से ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या अगर वे पारंपरिक अधिगम के इच्छुक हैं तो ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं।
- ◆ दस जिले शामिल हैं- रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगाँव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, महासमुंद।

निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

- इसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना से निर्माण श्रमिक की मृत्यु या विकलांगता के बाद उनके परिवारों को वित्तीय लाभ मिल सकेगा।
- पात्रता:
 - ◆ 18 से 60 वर्ष की आयु के निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।
 - ◆ निर्माण श्रमिक को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना चाहिये।
- लाभ:
 - ◆ सामान्य मृत्यु पर- ₹ 1,00,000
 - ◆ कार्य स्थल पर मृत्यु- ₹ 5,00,000
 - ◆ कार्य स्थल पर स्थायी विकलांगता- ₹ 2,50,000

केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा राज्यवार वार्ता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र पर राज्यों के साथ परामर्श शुरू किया तथा दो राज्यों छत्तीसगढ़ और असम के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की।

मुख्य बिंदु:

- चर्चा के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें **दलहन, तिलहन, बागवानी** आदि को बढ़ावा देना शामिल है
- केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी
- खरीफ सीजन में **खाद, बीज** आदि की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी।

खरीफ सीजन

- फसलें जून से जुलाई तक बोई जाती हैं और उनकी कटाई सितंबर-अक्तूबर के बीच की जाती है
- फसल: चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूँग, उड़द, कपास, जूट, मूँगफली, सोयाबीन आदि।
- राज्य: असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र।

सिंगल विंडो सिस्टम 2.0**चर्चा में क्यों ?**

हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्योग स्थापित करने के लिये आवश्यक विभिन्न मंजूरीयों के त्वरित अनुमोदन हेतु 'सिंगल विंडो सिस्टम' (SWS) के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया।

मुख्य बिंदु:

- सरकार निवेशकों और नए उद्योगपतियों की सुविधा के लिये त्वरित मंजूरी तथा अनुमोदन को प्राथमिकता देगी। **सुशासन** एवं **भ्रष्टाचार के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति** सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- ◆ ऑनलाइन सुविधा मंजूरी और अनुमोदन प्रदान करने में प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम करके प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायता करती है।
- सिंगल विंडो सिस्टम (SWS) 2.0 अपने पोर्टल पर 16 विभागों की 100 से अधिक सुविधाएँ प्रदान करता है।
- ◆ आवेदक को केवल एक बार लॉगइन करना होगा और उसे दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि प्रक्रिया के दौरान किसी विभाग को जानकारी की आवश्यकता होती है, तो आवेदक लॉगइन करके पता कर सकता है।
- ◆ किसी भी कार्यालय से ऑफलाइन संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। **ई-चालान** के माध्यम द्वारा भुगतान किया जा सकता है। आवेदन-पत्रों के निस्तारण के लिये विभागीय अधिकारियों को ID और पासवर्ड दिये गए हैं।

स्कूलों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन**चर्चा में क्यों ?**

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थानीय भाषा तथा बोलियों को शामिल करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु

- यह आदिवासी क्षेत्रों में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP) 2020** को लागू करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय है।
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षा विभाग को 18 स्थानीय भाषाओं और बोलियों में द्विभाषी पुस्तकें विकसित करने तथा वितरित करने का निर्देश दिया था, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- ◆ व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है तथा इन क्षेत्रों में **कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने की योजना है।**
- ◆ स्थानीय बोलियों में सादी भाषा भी शामिल है, जिसे आदिवासी बहुल जशपुर ज़िले में प्राथमिक शिक्षा के लिये शुरू किया जा सकता है।

- NEP 2020 में त्रि-भाषा सूत्र यह अनिवार्य करता है कि भारत में प्रत्येक छात्र को तीन भाषाएँ सीखनी चाहिये- जिनमें से दो मूल भारतीय भाषाएँ होनी चाहिये, जिसमें एक क्षेत्रीय भाषा शामिल हो, और तीसरी अंग्रेज़ी हो।
- ◆ इसका उद्देश्य छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं से परिचित कराकर राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करना तथा भाषायी विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है।
- ◆ इसका उद्देश्य छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं से परिचित कराकर राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करना तथा भाषायी विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है।
- रायपुर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में बच्चों को स्कूलों में दाखिला लेने हेतु पत्रोत्साहित करने के लिये शाला प्रवेशोत्सव मनाया जाता है।
- ◆ छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी ज़िले जशपुर के बगिया गाँव में राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव वर्ष 2024 का उद्घाटन किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का उद्देश्य भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं से निपटना है।
- इसमें शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव, इसके नियमन और प्रबंधन सहित, एक आधुनिक प्रणाली स्थापित करने का आह्वान किया गया है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं मूल्यों का सम्मान करते हुए सतत् विकास लक्ष्य 4 (SDG4) सहित 21वीं सदी के शैक्षिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो।
- इसने वर्ष 1992 में संशोधित चौतीस वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (NPE 1986/92) का स्थान लिया है।

सुशासन और अभिसरण विभाग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, सुशासन और सार्वजनिक मुद्दों के समाधान के लिये एक अलग "सुशासन एवं अभिसरण विभाग" बनाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि विभाग अब ई-समीक्षा, ई-लोक सेवा गारंटी और डिजिटल सचिवालय को शामिल करेगा, जो वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग का हिस्सा हैं।
- छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में संशोधन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी गई।
- मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नया रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिये पंजीयन की तिथि भी बढ़ा दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP) 2020

- परिचय:
 - ◆ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य "भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना" है। यह स्वतंत्रता के बाद से भारत में शिक्षा के ढाँचे में किया गया तीसरा बड़ा बदलाव है।
 - इससे पहले दो शिक्षा नीतियाँ वर्ष 1968 और वर्ष 1986 में लाई गई थीं।
- मुख्य विशेषताएँ:
 - ◆ पूर्व-प्राथमिक स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।
 - ◆ 3-6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना।
 - ◆ नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4) क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 तथा 14-18 वर्ष के आयु समूहों के अनुरूप है।
 - इसमें स्कूली शिक्षा के चार चरण शामिल हैं: आधारभूत चरण (5 वर्ष), प्रारंभिक चरण (3 वर्ष), मध्य चरण (3 वर्ष) और माध्यमिक चरण (4 वर्ष)।

- ◆ कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम तथा पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं;
- ◆ बहुभाषिकता और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर।
- ◆ एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, **PARAKH** (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिये ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना।
- ◆ वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिये एक अलग लिंग समावेशन निधि एवं विशेष शिक्षा क्षेत्र।

छत्तीसगढ़ विकास योजनाओं की समीक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के लिये विद्युत तथा शहरी विकास क्षेत्र में चल रही वर्तमान योजनाओं एवं प्रस्तावों की समीक्षा की।

मुख्य बिंदु:

- बैठक में केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ के विकास में तेज़ी आएगी।
- बैठक में जिन योजनाओं की समीक्षा की गई उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और आवासन एवं शहरी मामलों के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन शामिल हैं।

पीएम स्वनिधि (PM-SVANidhi)

- इसे 1 जून, 2020 को लॉन्च किया गया था।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अर्थात् यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित योजना है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
 - ◆ कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना
 - ◆ नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना
 - ◆ डिजिटल लेन-देन हेतु पुरस्कृत करना
- क्रमशः 10,000 रुपए और 20,000 रुपए के पहले एवं दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रुपए तक के तीसरे सावधि ऋण की शुरुआत की गई है।
- यह ऋण संपार्श्विक या कोलेट्रल के बिना प्रदान किया जाएगा।

अमृत योजना (AMRUT Scheme)

- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation- AMRUT) 25 जून, 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 60% शहरी आबादी को कवर किया गया।
- मिशन का लक्ष्य बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना और चयनित शहरों क्षेत्र में सुधारों को लागू करना है, जिसमें जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, हरित स्थान, गैर-मोटर चालित परिवहन तथा क्षमता निर्माण शामिल हैं।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM)

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे जून 2015 में "स्मार्ट सॉल्यूशंस" के अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता और स्वच्छ तथा संवहनीय वातावरण प्रदान करने के लिये, 100 शहरों के आवश्यक बुनियादी ढाँचे को बदलने के लिये प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य सतत और समावेशी विकास के माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

वित्त आयोग से छत्तीसगढ़ के लिये विशेष अनुदान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य की बड़ी जनजातीय आबादी, चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों और कुछ क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विशेष केंद्रीय अनुदान का अनुरोध किया था।

- यह मांग 16वें वित्त आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान की गई।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने आयोग को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेज़ी से किये जा रहे विकास कार्यों और माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये उठाए जा रहे प्रभावी कदमों की जानकारी दी।
- ◆ 'नियद नेल्लानार योजना' के तहत इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत् और जल जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- ◆ हालाँकि इन क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बुनियादी ढाँचे के विकास पर अतिरिक्त व्यय होता है।
- खनिज समृद्ध राज्य में खनन गतिविधियों के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये अतिरिक्त व्यय किया गया।
- ◆ उपभोग आधारित गंतव्य कर प्रणाली के रूप में GST (वस्तु एवं सेवा कर) के कारण, खनन गतिविधियों का वास्तविक लाभ छत्तीसगढ़ के बजाय उन राज्यों को मिल रहा है जहाँ खनिज मूल्य संवर्द्धन और खपत होती है।

नियद नेल्लानार योजना

- नियद नेल्लानार, जिसका अर्थ है "आपका अच्छा गाँव" अथवा "योर गुड विलेज" स्थानीय दंडामी बोली (दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली) है।
- इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गाँवों में सुविधाएँ और लाभ प्रदान किये जाएंगे।
- ◆ बस्तर में 14 नये सुरक्षा कैंप स्थापित किये गए हैं। ये शिविर नई योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में भी सहायता करेंगे। नियद नेल्लानार के तहत ऐसे गाँवों में लगभग 25 बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

वित्त आयोग

- भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- ◆ इसका प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है।
- 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर, 2017 को किया गया था। इसने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्टों के माध्यम से 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाली छह वर्षों की अवधि को कवर करने वाली सिफारिशें कीं।
- ◆ 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मान्य हैं।

माओवादी विद्रोह में कमी

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2024 में भारत में माओवाद से संबंधित 162 मृत्यु हुईं, जिनमें से छत्तीसगढ़ में 141 मृत्यु हुईं।

- यह वर्ष 2004 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) (CPI-M) की स्थापना के बाद से मुख्यतः आदिवासी बहुल राज्य में चरमपंथियों के लिये सबसे अधिक दुर्घटनाओं में से एक है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2009 में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के CoBRA बल और छत्तीसगढ़ पुलिस के "सर्च तथा कोंब" अभियान के तहत शुरू किये गए "ऑपरेशन ग्रीन हंट" के कारण भारत में माओवादी गतिविधियों में कमी आई।

- यद्यपि माओवादियों की मृत्यु की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन सुरक्षा बल कर्मियों की मृत्यु में कमी आई है।
- ◆ वर्ष 2024 में उग्रवाद में 14 सुरक्षा बल कर्मियों की मृत्यु हुई, जबकि वर्ष 2007 में यह संख्या सर्वाधिक 198 थी।
- ◆ वर्ष 2014 के बाद से नागरिकों की मृत्यु की संख्या भी सबसे कम रही है, माओवादी हमलों में 23 लोग मारे गए।
- गहन अभियान के कारण बीजापुर और पड़ोसी सुकमा में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 20 शिविर हैं।
- कांकेर में BSF और जिला रिजर्व गार्ड के संयुक्त अभियान में एक शीर्ष कमांडर समेत 29 माओवादी मारे गए। दंतेवाड़ा, जिसे वर्ष 2021 में 'माओवादी मुक्त' घोषित किया गया है, में वर्ष 2024 में केवल 15 माओवादी मारे गए।

प्रेहाउंड्स

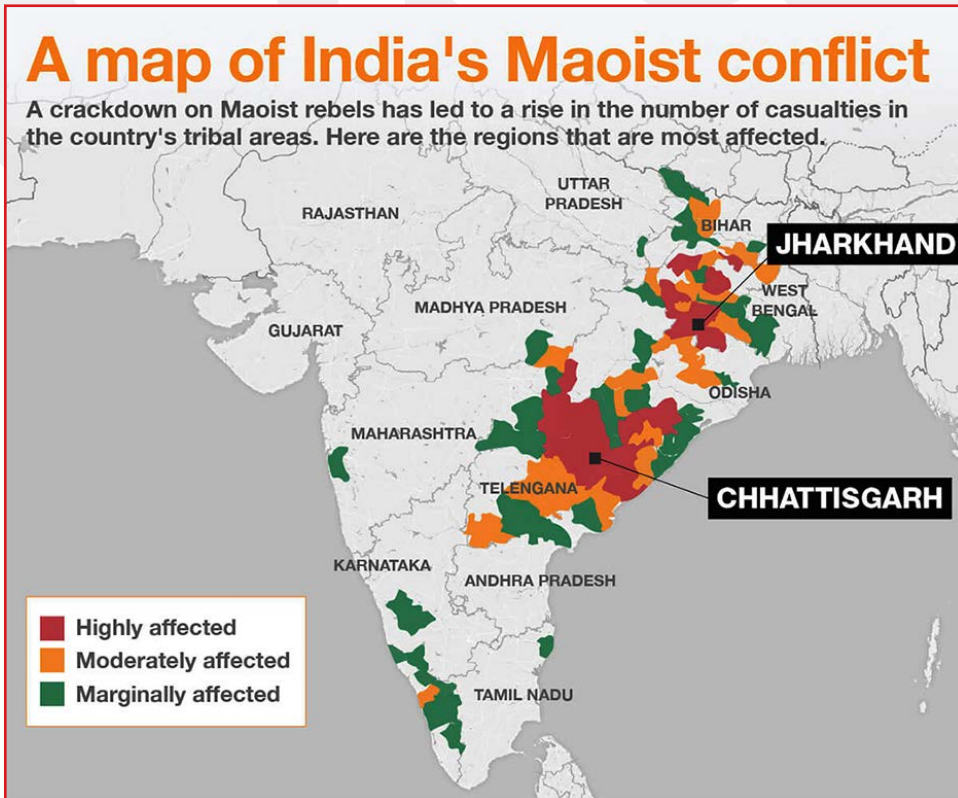
- यह एक विशिष्ट माओवादी विरोधी बल है जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में IPS अधिकारी के.एस.व्यास ने आंध्र प्रदेश में बढ़ते माओवादी खतरे से निपटने के लिये की थी।
- इसके सदस्य गुरिल्ला और वन युद्ध में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं।

ऑपरेशन ग्रीन हंट

- ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सलवादियों के विरुद्ध अर्द्धसैनिक बलों और राज्य बलों द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था।
- यह अभियान नवंबर 2009 में "रेड कॉरिडोर" के 5 राज्यों में शुरू हुआ।

रेड कॉरिडोर

- रेड कॉरिडोर भारत के मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भागों का वह क्षेत्र है जो गंभीर नक्सलवादी-माओवादी विद्रोह का अनुभव करता है।
- इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल राज्य शामिल हैं।



छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटेरियम

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल/प्लेनेटेरियम उग्रवाद प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में स्थापित किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- यह पहल दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) की सहायता से की गई है।
- संस्कृति मंत्रालय की विज्ञान एवं संस्कृति संवर्द्धन योजना, 2021 के अंतर्गत दंतेवाड़ा के कारली में डिजिटल तारामंडल स्थापित करने की योजना जल्द ही शुरू होगी
- जिला प्रशासन ने प्लेनेटेरियम के लिये सहयोग का अनुरोध किया और श्रेणी III (5 लाख से कम जनसंख्या) के अंतर्गत पूर्ण वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।
- इस पहल में शैक्षिक उन्नति, वैज्ञानिक चेतना, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति के साथ-साथ आकर्षक दृश्य-श्रव्य प्रयोग जैसे विभिन्न तत्व शामिल हैं
- प्लेनेटेरियम के निर्माण के लिये 7.95 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।
- घने जंगलों के बीच बसा यह डिजिटल प्लेनेटेरियम एक प्रमुख पर्यटन पहल होगी
- यह स्थानीय बच्चों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भावी पीढ़ियों को अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने के लिये प्रेरित करेगा।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (National Council of Science Museums- NCSM)

- वर्ष 1978 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) की स्थापना राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालयों के लिये एक केंद्रीय समन्वय एजेंसी के रूप में की गई थी
- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के साथ संयुक्त रूप से संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान है
- NCSM विज्ञान केंद्रों और संग्रहालयों का विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो एक ही प्रशासनिक छत्र के तहत कार्य करता है।

छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटेरियम

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल/प्लेनेटेरियम उग्रवाद प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में स्थापित किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- यह पहल दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) की सहायता से की गई है।
- संस्कृति मंत्रालय की विज्ञान एवं संस्कृति संवर्द्धन योजना, 2021 के अंतर्गत दंतेवाड़ा के कारली में डिजिटल तारामंडल स्थापित करने की योजना जल्द ही शुरू होगी
- जिला प्रशासन ने प्लेनेटेरियम के लिये सहयोग का अनुरोध किया और श्रेणी III (5 लाख से कम जनसंख्या) के अंतर्गत पूर्ण वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।
- इस पहल में शैक्षिक उन्नति, वैज्ञानिक चेतना, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति के साथ-साथ आकर्षक दृश्य-श्रव्य प्रयोग जैसे विभिन्न तत्व शामिल हैं

- प्लेनेटेरियम के निर्माण के लिये 7.95 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।
- घने जंगलों के बीच बसा यह डिजिटल प्लेनेटेरियम एक प्रमुख पर्यटन पहल होगी
- यह स्थानीय बच्चों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भावी पीढ़ियों को अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने के लिये प्रेरित करेगा।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (National Council of Science Museums- NCSM)

- वर्ष 1978 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) की स्थापना राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालयों के लिये एक केंद्रीय समन्वय एजेंसी के रूप में की गई थी
- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के साथ संयुक्त रूप से संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान है
- NCSM विज्ञान केंद्रों और संग्रहालयों का विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो एक ही प्रशासनिक छत्र के तहत कार्य करता है।

मलेरिया से निपटने के लिये छत्तीसगढ़ की पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को मानसून के दौरान में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिये सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिये हैं

- परिणामस्वरूप, बस्तर सहित पूरे राज्य में मलेरिया के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।

मुख्य बिंदु:

- बस्तर संभाग के घने वनों और दुर्गम इलाकों में मलेरिया जैसी बीमारियों को रोकना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है
- मलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत, 2020 से 2023 तक मलेरिया उन्मूलन अभियान के नौ चरणों के दौरान मलेरिया सकारात्मकता (Positivity) दर 4.60% से घटकर 0.51% हो गई।
- ◆ दसवाँ चरण 5 जुलाई, 2024 को समाप्त हुआ और इस अभियान के तहत 22 जिलों में 16.97 लाख कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियाँ वितरित की गईं।
- स्वास्थ्य विभाग की वर्ष 2024 की पहली छमाही के लिये मलेरिया मामले की रिपोर्ट में निम्नलिखित संख्या में मामले सामने आए: बस्तर में 1,660, बीजापुर में 4,441, दंतेवाड़ा में 1,640, कांकेर में 259, कोंडागाँव में 701, नारायणपुर में 1,509 और सुकमा में 1,144।
- ◆ परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य विभाग ने मामले की निगरानी बढ़ा दी है और सभी जिलों में उपचार सुविधाओं को मजबूत किया है।

मलेरिया

- मलेरिया एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है।
- ◆ प्लास्मोडियम परजीवी की पाँच प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं और इनमें से दो प्रजातियाँ- पी. फाल्सीपेरम तथा पी. विवैक्स- सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करती हैं।
- मलेरिया मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज़ मच्छर के काटने से फैलता है।
- ◆ संक्रमित व्यक्ति को काटने से मच्छर संक्रमित हो जाता है और इससे मलेरिया के परजीवी मच्छर द्वारा काटे गए अगले व्यक्ति के रक्तप्रवाह में प्रवेश करते हैं। ये परजीवी यकृत तक जाते हैं, परिपक्व होते हैं तथा फिर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं।
- मलेरिया के लक्षणों में बुखार और पलू जैसे लक्षण शामिल हैं, जैसे- ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द तथा थकान आदि। उल्लेखनीय है कि मलेरिया का इलाज संभव है एवं रोकथाम भी संभव है।

केटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक में खनन

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (Chhattisgarh Environment Conservation Board- CECB) ने हसदेव अरंड क्षेत्र में परसा ईस्ट-केंटे बसन (Parsa East-Kente Basan- PEKB), परसा और केटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक परियोजनाओं के लिये सार्वजनिक परामर्श आयोजित करने के लिये एक परिपत्र जारी किया है।

मुख्य बिंदु

- कुछ स्थानीय लोगों ने परियोजना के प्रति समर्थन व्यक्त किया है तथा विकास के लिये इसके संभावित लाभों की ओर इंगित किया है, जबकि अन्य ने इस पर अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं।
- ◆ वर्ष 2021 में बनाए गए **लेमरू हाथी रिज़र्व** के दस किलोमीटर के भीतर एक खनन परियोजना क्षेत्र है। खनन के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में **मानव- हाथी संघर्ष** में वृद्धि होगी ।
- सूत्रों के अनुसार, सार्वजनिक सुनवाई 2 अगस्त 2024 को होगी, क्योंकि पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिये यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है।

हसदेव अरंड वन



- छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित हसदेव अरंड नामक विशाल वन अपनी जैवविविधता और कोयला निक्षेपों के लिये जाना जाता है।
- यह वन कोरबा, सुजापुर और सरगुजा जिलों के अंतर्गत आता है जहाँ जनजातीय जनसंख्या काफी अधिक है।
- **महानदी** की सहायक नदी हसदेव नदी यहाँ से होकर प्रवाहित होती है।
- हसदेव अरंड **मध्य भारत का सबसे बड़ा अक्षुण्ण वन है, जिसमें प्राचीन साल (शोरिया रोबस्टा) और सागौन के वन शामिल हैं।**
- यह एक प्रसिद्ध प्रवासी गलियारा है और यहाँ **हाथियों** की उपस्थिति काफी अधिक है।

लेमरू हाथी रिज़र्व

- यह रिज़र्व छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में स्थित है।
- इस रिज़र्व का उद्देश्य हाथियों को एक स्थायी निवास स्थान प्रदान करने के अलावा **मानव-पशु संघर्ष** और संपत्ति के नुकसान को कम करना है।
- इससे पूर्व, राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [Wild Life (Protection) Act,1972]** की धारा 36 A के तहत रिज़र्व (संरक्षण रिज़र्व) को अधिसूचित किया था।
 - ◆ धारा 36A में एक विशेष प्रावधान है जो केंद्र सरकार को अधिसूचना की प्रक्रिया में अपनी बात कहने का अधिकार देता है, यदि संरक्षण रिज़र्व के रूप में अधिसूचित की जाने वाली भूमि में केंद्र का क्षेत्र शामिल है।
 - ◆ **WLPA के अंतर्गत हाथी रिज़र्व को मान्यता नहीं दी गई है।**

विकसित भारत बजट ब्लूप्रिंट

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि **केंद्रीय बजट, 2024** में 'अमृतकाल विज्ञान- 2047' की स्पष्ट झलक दिखाई देती है।

मुख्य बिंदु:

- **छत्तीसगढ़ का प्रावधान:** बजट में कृषि के लिये 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जिससे किसानों के लिये रोजगार और समृद्धि में नई क्रांति का वादा किया गया है
- **मुद्रा लोन और इंटरनेशिप:** इस योजना में **मुद्रा लोन को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए** करना तथा **5 करोड़ युवाओं** को शीर्ष कंपनियों में इंटरनेशिप प्रदान करना शामिल है
- **महिलाएँ और लड़कियाँ:** महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं, **आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा** को बढ़ावा देने के लिये **3 लाख करोड़ रुपए** आवंटित किये गए हैं
- इस बजट का उद्देश्य **छत्तीसगढ़ को 'आत्मनिर्भर' और समृद्ध बनाना** है, जो विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

छत्तीसगढ़ सरकार एवं ऑपरेशन प्रहार

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ में **प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री** के पदभार ग्रहण करने के बाद से नक्सलियों की हत्या, गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण में **पाँच गुना वृद्धि** हुई है।

- इसके साथ ही राज्य की **मनमानी शक्ति** और "ऑपरेशन प्रहार" के तहत **फर्जी मुठभेड़ों** के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।
- **मुख्य बिंदु**
- **ऑपरेशन प्रहार:** यह छत्तीसगढ़ में **माओवादियों** के विरुद्ध चल रहा एक **आतंकवाद विरोधी अभियान** है।
- **उद्देश्य और रणनीति:** ऑपरेशन प्रहार का मुख्य लक्ष्य प्रमुख **माओवादी नेताओं** को निशाना बनाना तथा उन्हें निष्प्रभावी करना है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे स्थानीय युवाओं का जबरन मत परिवर्तन (ब्रेनवॉश) कर रहे हैं और उन्हें भर्ती कर रहे हैं।
 - ◆ हाल ही में इस अभियान को और तेज़ कर दिया गया है तथा इसे पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तारित किया जाएगा।
- **स्थानीय आबादी पर प्रभाव:** हालाँकि यह अभियान माओवादी विद्रोहियों को लक्ष्य करता है, लेकिन स्थानीय आदिवासी समुदायों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ हैं तथा ऐसी खबरें हैं कि अभियान के दौरान गैर-माओवादी आदिवासी भी प्रभावित हुए हैं।

छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने किया सरेंडर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में पाँच नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया जिनपर कुल 19 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- नक्सलियों ने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि वे अपने से बड़े नक्सलियों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों और अमानवीय तथा निरर्थक माओवादी विचारधारा से हताश हो चुके थे।
- राज्य सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति और कल्याणकारी योजनाओं के अनुसार, सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 25-25 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई तथा उनका पुनर्वास भी किया जाएगा।

नक्सलवादियों पर नियंत्रण के लिये की गई सरकारी पहल

- **समाधान (SAMADHAN) सिद्धांत** वामपंथी उग्रवाद की समस्या का एकमात्र समाधान है। इसमें विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई अल्पकालिक नीति से लेकर दीर्घकालिक नीति तक सरकार की संपूर्ण रणनीति शामिल है। **समाधान (SAMADHAN) का पूर्ण रूप है:**
 - ◆ S- स्मार्ट लीडरशिप
 - ◆ A- एग्रेसिव स्ट्रेटेजी
 - ◆ M- मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग
 - ◆ A- एक्शनबल इंटेलिजेंस
 - ◆ D- डैशबोर्ड बेस्ड KPI (की परफॉरमेंस इंडिकेटर) एंड KRA (की रिजल्ट एरिया)
 - ◆ H- हॉर्नेसिंग टेक्नोलॉजी
 - ◆ A- एक्शन प्लान फॉर इच थिएटर
 - ◆ N- नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग
- 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना: इसमें बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल है जिसमें सुरक्षा उपाय, विकास पहल और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना शामिल है।
 - ◆ गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) बटालियनों की तैनाती, हेलीकाप्टरों एवं UAV के प्रावधान और भारतीय आरक्षित वाहिनी (IRB) आदि की मंजूरी के माध्यम से बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों का समर्थन कर रहा है।
 - ◆ राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिये पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (MPF), सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना तथा विशेष अवसरचरणात्मक ढाँचा योजना (SIS) के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।
 - ◆ विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) योजना के तहत अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (LWE) ज़िलों को विकास के लिये धन भी प्रदान किया जाता है।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम: वर्ष 2018 में लॉन्च किये गए आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम का उद्देश्य उन ज़िलों में तेज़ी से बदलाव लाना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है।
- ग्रेहाउंड्स: ग्रेहाउंड्स को वर्ष 1989 में विशिष्ट नक्सल विरोधी बल के रूप में स्थापित किया गया था।
- ऑपरेशन ग्रीन हंट: इसे वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी।
- बस्तरिया बटालियन: छत्तीसगढ़ में CRPF ने एक बस्तरिया बटालियन की स्थापना की, जिसके लिये स्थानीय आबादी से सिपाहियों की भर्ती की गई, जो भाषा और इलाके से परिचित थे तथा खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकते थे।
 - ◆ इस इकाई में अब 400 सिपाही (Recruits) हैं और इसका नियमित रूप से छत्तीसगढ़ में संचालन किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में खनन हेतु वनों की कटाई

चर्चा में क्यों ?

केंद्र के अनुसार वन्यजीव और जैवविविधता संस्थाओं ने संबद्ध क्षेत्र में खनन गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की सिफारिश नहीं की जिसके चलते हसदेव अरण्य वनों में खनन गतिविधियों के लिये लगभग 273,000 अतिरिक्त वृक्षों को काटे जाने की आशंका है।

प्रमुख बिंदु

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने देश के दो सबसे विवादास्पद पर्यावरणीय मुद्दों पर जानकारी प्रदान की जिसमें छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य में वनों की कटाई तथा नीति आयोग की अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह परियोजना में ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास शामिल हैं।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून को संपूर्ण हसदेव-अरण्य कोलफील्ड्स क्षेत्र का जैवविविधता मूल्यांकन अध्ययन करने के लिये नियुक्त किया था।
 - ◆ अध्ययन किया गया और तत्पश्चात् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई
 - ◆ रिपोर्ट के अनुसार, परसा ईस्ट केते बासेन खदान हेतु 94,460 वृक्ष काटे गए जबकि प्रतिपूरक वनीकरण, खदान सुधार और स्थानांतरण के रूप में 5.3 मिलियन से अधिक वृक्षों का रोपण किया गया
 - ◆ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हसदेव अरण्य में आगामी वर्षों में खनन के लिये 273,757 वृक्षों की कटाई की जानी है।
- हसदेव अरण्य मध्य भारत में सर्वाधिक सघन वनों के सबसे बड़े सन्निहित विस्तारों में से एक है, जो 170,000 हेक्टेयर में विस्तृत है और इसमें 23 कोयला ब्लॉक हैं
 - ◆ वर्ष 2009 में, पर्यावरण मंत्रालय ने हसदेव अरण्य को इसके समृद्ध वन क्षेत्र के कारण खनन के लिये “नो-गो” ज़ोन के रूप में वर्गीकृत किया था किंतु यहाँ खनन की पुनः अनुमति दे दी गई क्योंकि इसमें किसी नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

हसदेव अरण्य वन



- छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में विस्तृत हसदेव अरण्य वन अपनी जैवविविधता और कोयला निक्षेपों के लिये जाना जाता है।
- यह वन कोरबा, सुजापुर और सरगुजा जिलों के अंतर्गत आता है जहाँ जनजातीय जनसंख्या काफी अधिक है।
- महानदी की सहायक नदी हसदेव नदी यहाँ से होकर प्रवाहित होती है।
- हसदेव अरंड मध्य भारत का सबसे बड़ा अक्षुण्ण वन है, जिसमें प्राचीन साल (शोरिया रोबस्टा) और सागौन के वन शामिल हैं।
- इसकी भूमिका प्रवासी गलियारे के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ महत्वपूर्ण संख्या में हाथी पाए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने किया सरेंडर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में पाँच नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया जिनपर कुल 19 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- नक्सलियों ने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि वे अपने से बड़े नक्सलियों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों और अमानवीय तथा निरर्थक माओवादी विचारधारा से हताश हो चुके थे।
- राज्य सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति और कल्याणकारी योजनाओं के अनुसार, सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 25-25 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई तथा उनका पुनर्वास भी किया जाएगा।

नक्सलवादियों पर नियंत्रण के लिये की गई सरकारी पहल

- समाधान (SAMADHAN) सिद्धांत वामपंथी उग्रवाद की समस्या का एकमात्र समाधान है। इसमें विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई अल्पकालिक नीति से लेकर दीर्घकालिक नीति तक सरकार की संपूर्ण रणनीति शामिल है। समाधान (SAMADHAN) का पूर्ण रूप है:
 - ◆ S- स्मार्ट लीडरशिप
 - ◆ A- एग्रेसिव स्ट्रेटेजी
 - ◆ M- मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग
 - ◆ A- एक्शनेबल इंटेलिजेंस
 - ◆ D- डैशबोर्ड बेस्ड KPI (की परफॉरमेंस इंडिकेटर) एंड KRA (की रिजल्ट एरिया)
 - ◆ H- हॉर्नेस्सिंग टेक्नोलॉजी
 - ◆ A- एक्शन प्लान फॉर इच थिएटर
 - ◆ N- नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग
- 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना: इसमें बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल है जिसमें सुरक्षा उपाय, विकास पहल और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना शामिल है।
 - ◆ गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) बटालियनों की तैनाती, हेलीकाप्टरों एवं UAV के प्रावधान और भारतीय आरक्षित वाहिनी (IRB) आदि की मंजूरी के माध्यम से बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों का समर्थन कर रहा है।
 - ◆ राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिये पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (MPF), सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना तथा विशेष अवसरचरणात्मक ढाँचा योजना (SIS) के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।
 - ◆ विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) योजना के तहत अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (LWE) जिलों को विकास के लिये धन भी प्रदान किया जाता है।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम: वर्ष 2018 में लॉन्च किये गए आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम का उद्देश्य उन जिलों में तेजी से बदलाव लाना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है।

- ग्रेहाउंड्स: ग्रेहाउंड्स को वर्ष 1989 में विशिष्ट नक्सल विरोधी बल के रूप में स्थापित किया गया था।
- ऑपरेशन ग्रीन हंट: इसे वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी।
- बस्तरिया बटालियन: छत्तीसगढ़ में CRPF ने एक बस्तरिया बटालियन की स्थापना की, जिसके लिये स्थानीय आबादी से सिपाहियों की भर्ती की गई, जो भाषा और इलाके से परिचित थे तथा खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकते थे।
- ◆ इस इकाई में अब 400 सःिपाही (Recruits) हैं और इसका नियमित रूप से छत्तीसगढ़ में संचालन किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ सहित दस राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की।

- असम से पूर्व लोकसभा सदस्य रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

मुख्य बिंदु

- वह वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का स्थान लेंगे, जिन्हें फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया था।
- राज्यपाल:
 - ◆ राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग VI में निहित हैं।
 - ◆ अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
 - ◆ राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में दोहरी भूमिका अदा करता है।
 - ◆ वह भारतीय राजनीति की संघात्मक प्रणाली का हिस्सा है और संघ एवं राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है।
 - ◆ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिये पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं।

छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ सहित दस राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की।

- असम से पूर्व लोकसभा सदस्य रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

मुख्य बिंदु

- वह वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का स्थान लेंगे, जिन्हें फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया था।
- राज्यपाल:
 - ◆ राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग VI में निहित हैं।
 - ◆ अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
 - ◆ राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में दोहरी भूमिका अदा करता है।
 - ◆ वह भारतीय राजनीति की संघात्मक प्रणाली का हिस्सा है और संघ एवं राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है।
 - ◆ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिये पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं।

